भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1526 का उत्तर

चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों को बंद करना

1526. श्रीमती जोबा माझी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चक्रधरपुर रेल मंडल में कोविड-19 से पहले चलने वाली कई यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि चक्रधरपुर रेल मंडल बहुत लाभदायक है और स्थानीय मजदूरों और किसानों को यात्री ट्रेनों के बंद होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर के नवीनीकरण कार्य के कारण अपनी दुकानें खोने वाले 50 परिवारों के लिए सरकार द्वारा कोई पुनर्वास योजना प्रस्तावित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेलवे ने अनुरक्षण कॉरिडोर ब्लॉक बनाकर बेहतर यात्री सुरक्षा प्रदान करने, मौजूदा समय सारणी में टकराव को कम करने आदि के उद्देश्य से, आईआईटी-बॉम्बे की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाने का काम शुरू किया है।

समय सारणी को युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में कुछ रेलगाड़ियों की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर भारतीय रेल पर नई गाड़ी सेवाएं शुरू करना सतत् प्रक्रिया है।

(घ): रेल मंत्रालय ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, भूदृश्य निर्माण आदि जैसी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान आवश्यकता के अनुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य रेलवे स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

अब तक भारतीय रेल में चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन सहित 1324 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। स्टेशनों के विभिन्न भागों में भूमि का विकास स्टेशन की मांग और आवश्यकताओं के आधार पर एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। रेलवे और लाइसेंस/लीज पर रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के बीच समझौते के प्रावधानों के अनुसार, पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि खाली करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है।

*****